INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 7, July 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का अध्ययनः एक विश्लेषणात्मक शोध

कु० डौली[1], प्रो० प्रतिमा गुप्ता[2]
पीएच.डी शोधार्थी, प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग,
राजा बलवंत सिंह कॉलेज, आगरा,
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, भारत
dollysingh3459@gmail.com

सारांशः किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को सस्ती और सुलभ ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में इस योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राज्य की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यह अध्ययन राज्य में केसीसी योजना के कार्यान्वयन, प्रभाव और चुनौतियों का विश्लेषण करता है। अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों जैसे नाबार्ड, आरबीआई, कृषि मंत्रालय, शोध पत्रों तथा सरकारी रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। शोध से ज्ञात होता है कि इस योजना ने किसानों की आय बढ़ाने, साहूकारों पर निर्भरता कम करने और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सकारात्मक योगदान दिया है। साथ ही, इसने वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया है। हांलाकि, जागरूकता की कमी, जटिल बैंकिग प्रक्रियाएं, ऋण सीमा की अपर्याप्तता और पुनर्भुगतान संबंधी समस्याएं अभी भी प्रमुख बाधाएं हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि यदि योजना के क्रियान्वयन में सुधार किया जाए और किसानों को अधिक जानकारी व सुविधा प्रदान की जाए, तो यह योजना उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बना सकती है।

मुख्य शब्दः किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी), कृषि ऋण, उत्तर प्रदेश कृषि (उ०प्र), ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन, कृषि उत्पादन, संस्थागत ऋण, छोटे एंव सीमांत किसान, कृषि विकास, बैंकिंग सुविधा, राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय रिर्ज़व बैंक (आरबीआई), ग्रामीण अर्थव्यवस्था, फसल ऋण, कृषि निवेश.

1. प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है, देश की बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। जहाँ लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ ही कृषि उत्पादन में आगे है। गेंहूँ, धान, गन्ना, आलू एंव दलहन उत्पादन में उ०प्र० का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्रों की प्रगति किसानों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है, और किसानों की आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से ऋण सुविधाओं की उपलब्धता से प्रभावित होती है।

भूतकाल में भारतीय किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों एंव महाजनों से ऊँची ब्याज पर ऋण लेने को विवश थे। जो अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते थें। इससे किसान ऋण के जाल में फँस जाते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जाती थी। किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे कृषि कार्यों हेतु आवश्यक संसाधन खरीद सकें।

उ०प्र० में केसीसी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरल एंव सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे कृषि कार्यों के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। यह योजना किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, कृषि यंत्र आदि खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराती है। वर्तमान शोध पत्र में उ०प्र० में इस योजना का व्यापक प्रभाव एंव चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

1.1 किसान क्रेडिट कार्ड योजना का परिचय

केसीसी योजना की शुरूआत राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के सहयोग से की गई थी। इस योजना के अतंगर्त किसानों को बैंक द्वारा एक क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से किसान आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित सीमा तक ऋण प्राप्त कर सकता है।

योजना की प्रमुख्य विशेषताएँ

- किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।
- केसीसी योजना का पंजीकरण हेतु सरल आवेदन प्रक्रिया।
- फसल चक्र के अनुसार पुनर्भुगतान की सुविधा।
- दुर्घटना बीमा एंव फसल बीमा का लाभ।
- अल्पकालिक एंव दीर्घकालिक ऋण उपलब्धता।
- एटीएम एंव डिजिटल बैंकिंग की सुविधा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा कृषि क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना है।

2. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में उ०प्र० में केसीसी योजना के प्रभाव एंव कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक एंव विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। शोध सामग्री हेतु आवश्यक जानकारी विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, नाबार्ड, आरबीआई, कृषि मंत्रालय, शोध पत्रों, पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं तथा विश्वसनीय इंटरनेट स्त्रोतों से प्राप्त की गई है। उपलब्ध आँकड़ों का तुलनात्मक एुव व्याख्यात्मक विश्लेषण करके योजना की वास्तविक स्थिति, उपलब्धियों तथा समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य केसीसी योजना के माध्यम से किसानों को प्राप्त होने वाले लाभों, कृषि उत्पादन में हुए परिवर्तन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है।

3. शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- उ०प्र० में केसीसी योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।
- किसानों की आर्थिक स्थिति पर योजना के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- योजना से संबंधित समस्याओं एंव चुनौतियों की पहचान करना।
- योजना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

4. साहित्य समीक्षा

किसान क्रेडिट कार्ड योजना तथा किसानों के आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा समय–समय पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में योजनाओं के प्रभाव,दकिसानों की आय, कृषि उत्पादन, वित्तीय समावेशन तथा ग्रामीण विकास पर इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र से संबंधित प्रमुख अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है–

शर्मा एंव वर्मा (2025 द्वारा किए गए अध्ययन में केसीसी योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन, जोखिम प्रबंधन तथा संस्थागत विश्वास के संबंध का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि केसीसी योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई है।

जांगड़े (2024) इस अध्ययन से यह स्पष्ट है, कि केसीसी के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के बाद धारको की कृषि उत्पादकता एंव आय बढ़ाने में सहायक रही है केसीसी के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न ऋण सुविधाएँ पर्याप्त थी और केसीसी धारको को समय पर प्रदान की जाती थी। केसीसी से ऋणग्रस्तता कम करने में मदद मिली। अधिकांश किसान केसीसी से परिचित थे, लेकिन उन्हें केसीसी की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी नही थी।

नरभावर जी. सी. (2024) डांग जिले के किसानों में केसीसी योजनाओं की जागरूकता के स्तर में वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में लाभार्थीयों ने बताया कि केसीसी का लाभ उठाने के बाद उनकी आय में वृद्धि हुई तथा केसीसी के तहत दिए गए ऋणों ने उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों का अपनाने और फसल उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम बनाया है। कुछ किसानों ने केसीसी ऋणों की सहायता से डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम हुए है। इससे उनकी अतिरिक्त आय हुई और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। केसीसी लाभार्थीयों में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। अतः सरकार और सहकारी बैंकों को महिला किसानों को इस योजना सं जोड़ने के प्रयास करने चाहिए।

टी. महालक्ष्मी (2023) किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम किसानों को फसल उत्पादन और संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए समय पर पर्याप्त बैंकिंग प्रणाली सहायता प्रदान करता है। केसीसी कार्यक्रम से किसानों एंव उनकी कृषि दोनों लाभान्वित होते है। केसीसी कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों, इनपुट खरीद आदि के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। केसीसी योजना के परिणामस्वरूप किसानों की सामाजिक– आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। केसीसी में कुछ कमिंया भी है। यदि ये प्रतिबंध हटा दिए जाएँ तो किसानों की आजीविका में निस्संदेह सुधार होगा।

सिंह और राठोर (2023) इस अध्ययन का उद्देश्य किसानों में केसीसी की जानकारी के अभाव और भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी है। यह अध्ययन शोध पत्र, पत्रिकाओं, बेवसाइट आदि से लिया गया है। हमें किसानों में जागरूकता और प्रशिक्षण सेवाओं के माध्यम से किसानों में ज्ञान के अभाव को दूर करना चाहिए, अधिकांश अन्य अध्ययनों से यह देखा गया है। कि कुछ अन्य योजनाएँ अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लाभार्थी को उनका लाभ भी मिल रहा है।

डेहरिया, एल. (2023) किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में असमानताएं है। मध्य प्रदेश राज्य में कृषक परिवारों की अलग–अलग धारणाएं पायी गयी हैं। केसीसी लाभार्थी किसानों के अनुसार केसीसी की प्रक्रिया सरल नही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत नई–नई सुविधाओं को शामिल किया जाऐ, लेकिन किसानों में इन योजनाओं के लाभ के बारे में कोई जागरूकता उत्पन्न नही की गयी है। सरकार को जिला सहकारी बैंकों द्वारा केसीसी बनवाने तथा लेनदेन की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए, और बैंकों द्वारा योजनाओं के बारे में किसानों तक आवश्यक जानकारी पहुँचानी चाहिए।

वेरिया, ए. (2020) भारतीय सरकार यदि केसीसी योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गंभीर है। तो केसीसी ऋणों के लिए बैंकों को गारण्टी के रूप में आवश्यक राशि को प्रावधान करना होगा, ताकि सभी किसान जिनको संस्थागत ऋण की संतृप्ति सुनिश्चित करते हुए किरायेदार की सीमा, भूमि हीन किसानों की संख्या, कृषि में लगे वास्तविक जनसंख्या का मजूबत अनुमान प्रदान करेगा, तथा किसानों को लाभांवित करने के लिए बेहतर लक्षित नीतियों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भट्टाचार्जी और शर्मा (2020) इस शोध में 2017–2018 के दौरान इस अध्ययन के लिए शोध कार्य किया गया थ। जिससे नमूने के पहले चरण में दो ब्लॉक अर्थात मेडजीफेमा और चुनुकदिमा का चयन किया गया था। जिसने 85 उत्तरदाताओं को दोनों श्रेणी में चुना गया था। 40 केसीसी लाभार्थी 40 गैर–लाभार्थी और 5 बैंकिंग व्यक्ति उनकी राय, केसीसी ऋण प्रदान में आने वाली समस्या के लिए। शोध अध्ययन से पता

चलता है कि केसीसी लाभार्थी, गैर–लाभार्थी की तुलनाध्ध्ध में कम उम्र के पाये गये तथा केसीसी लाभार्थी की आय गैर–लाभार्थी की तुलना में अधिक थी।

5. उत्तर प्रदेश में कृषि की स्थिति

उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे महत्वपूर्ण कृषि राज्यों में गिना जाता है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित है तथा बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। यहाँ भूमि की उपजाऊ के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाते हैं। राज्य में गेहूँ, धान, गन्ना, आलू, तिलहन एंव दलहन जैसी फसलों का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है।

उ०प्र० में अधिकांश किसान छोटे एंव सीमांत वर्ग से संबंधित है। सीमित संसाधनों के कारण किसानों को कृषि निवेश हेतु ऋण की आवश्यकता पड़ती है। केसीसी योजना किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है।

6. उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन

उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन किसानों को समय पर एंव सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राज्य विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित करके किसानों को केसीसी योजना की जानकारी दी जाती है तथा नए केसीसी बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को भी केसीसी उपलब्ध कराने हेतु विशेष अभियान चलाए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में किसानों को संस्थागत ऋण सुविधा प्राप्त हुई है।

तालिका 6.1 उत्तर प्रदेश में केसीसी वितरण

वर्ष	जारी केसीसी (लाख में)	ऋण वितरण (लगभग करोड़ रु)
2019	150	45000
2020	170	50000
2021	190	58000
2022	210	65000
2023	230	72000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उ०प्र० में केसीसी योजना का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2019 से 2023 के बीच जारी किए गए केसीसी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही ऋण वितरण की कुल राशि में भी निरंतर वृद्धि देखी गई है। यह दर्शाता है कि किसानों का बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास बढ़ा रहा है।

हालांकि, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ समस्याएँ भी सामने आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मे कई किसानों को अभी भी योजना की पूरी जानकारी नही हैं। कई स्थानों पर बैंकिंग प्रक्रियाएँ जटिल होने के कारण किसानों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, छोटे किसानों के लिए ऋण सीमा कई बार पर्याप्त नही होती। इसके बावजूद केसीसी उ०प्र० में कृषि विकास एंव किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महतवपूर्ण पहल सिद्ध हुई है।

6.2 किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव

6.2.1 आर्थिक प्रभाव

केसीसी योजना ने उ०प्र० के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को समय पर एंव कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने लगा है, जिससे उनकी साहूकारों और महाजनों पर निर्भरता कम हुई है। पहले किसान ऊँचे ब्याज पर ऋण लेकर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन अब वे बैंकिंग प्रणाली से सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं। किसानों को कृषि निवेश हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलने से वे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा आधुनिक कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा किसानों की आय में भी सुधार देखा गया है। साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिरता बढ़ी है और वे कृषि संबंधी आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हुए हैं।

6.2.2 सामाजिक प्रभाव

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। किसानों की आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अब किसान अपने परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य एंव अन्य आवश्यक सुविधाओं पर अधिक खर्च करने में सक्षम हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होने से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है तथा किसानों में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ा है और वे बचत एंव वित्तीय प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं। इससे ग्रामीण समाज में आर्थिक एंव सामाजिक स्थिरता को मजबूत मिली है।

6.2.3 कृषि विकास पर प्रभाव

केसीसी योजना ने कृषि विकास को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध होने से वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने लगे हैं। उन्नत बीज, आधुनिक सिंचाई साधन, कृषि यंत्र एंव वैज्ञानिक खेती की पद्धतियों का उपयोग बढ़ा है, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त किसानों ने पशुपालन, डेयरी एंव अन्य कृषि सहायक गतिविधियों को भी अपनाना प्रारंभ किया है, जिससे उनकी अतिरिक्त आय में वृद्धि हुई है। योजना के कारण कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ा है और किसानों की उत्पादन क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है।

6.2.4 किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रमुख समस्याएँ

6.2.4.1 जागरूकता की कमी

- उ०प्र० के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनेक किसानों को केसीसी योजना की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- कुछ किसानों को योजना की आवेदन प्रक्रिया, ब्याज दर, पुनर्भुगतान अवधि तथा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सही जानकारी नहीं होती।
- अशिक्षा एंव वित्तीय जानकारी की कमी के कारण किसान बैंकिंग प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- कई बार सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल सीमित क्षेत्रों तक ही पहुँच पाती है, जिससे दूरदराज के किसान लाभ से वंचित रह जाते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जागरूकता अभियान एंव प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी भी एक बड़ी समस्या है।

6.2.4.2 जटिल बैंकिंग प्रक्रिया

- केसीसी प्राप्त करने के लिए किसानों को कई प्रकार की दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
- भूमि संबंधी दस्तावेज़, पहचान पत्र, बैंक खाता एंव अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होने से किसानों को कठिनाई होती है।
- छोटे ऐव सीमांत किसानों के पास कई बार आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं होते।
- बैंक शाखाओं में लंबी प्रक्रिया एंव कर्मचारियों की कमी के कारण ऋण स्वीकृति में देरी होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के कम शिक्षित किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया समझना कठिन होता है।

6.2.4.3 ऋण सीमा अपर्याप्त होना

- वर्तमान समय में कृषि लागत में वृद्धि हो रही है, जबकि कई किसानों के लिए निर्धारित ऋण सीमा पर्याप्त नही होती।
- बीज, उर्वरक, डीजल, सिंचाई एंव कृषि यंत्रों की बढ़ती कीमतों के कारण किसानों को अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है।
- छोटे एंव सीमांत किसानों को सीमित ऋण मिलने के कारण कृषि निवेश में कठिनाई होती है।
- ऋण सीमा कम होने से किसान आधुनिक कृषि तकनीकों एंव उन्नम संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते।
- बढ़ती मँहगाई एंव कृषि खर्चों को देखते हुए ऋण सीमा में समय–समय पर संशोधन की आवश्यकता है।

6.2.4.4 पुनर्भुगतान संबंधी समस्याएँ

- कृषि प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होने के कारण किसानों की आय स्थिर नहीं रहती।
- बाढ़, सूखा, अनियमित वर्षा एंव फसल खराब होने जैसी समस्याओं के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
- फसल खराब होने पर किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं।
- ऋण का पुनर्भुगतान न होने पर किसानों पर अतिरिक्त ब्याज एंव आर्थिक दबाव बढ़ जाता है।
- प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों के लिए ऋण पुनर्भुगतान अवधि में राहत की आवश्यकता होती है।

6.2.4.5 क्षेत्रीय असमानता

- उ०प्र० के सभी क्षेत्रों में केसीसी योजना का सामना रूप से लाभ नहीं पहुँच पाया है।
- पश्चिमी उ०प्र० में बैंकिंग सुविधाएँ एंव किसानों की जागरूकता अधिक होने के कारण योजना का प्रभाव बेहतर देखा गया है।
- पूर्वी एंव पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको शाखाओं की कमी के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी एंव डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का अभाव भी कठिनाई होती है।
- क्षेत्रीय असामनता के कारण राज्य के सभी किसानों को समान आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

6.2.4.6 सुधार हेत सुझाव

1. किसानों के मध्य जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
2. आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
3. डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
4. छोटे एंव सीमांत किसानों के लिए ऋण सीमा बढ़ाई जाए।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाए।

7. निष्कर्ष

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) उ०प्र० के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना सिद्ध हुई है। इस योजना ने किसानों को संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन एंव आय में वृद्धि करने में सहायता प्रदान की है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में इस येाजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हांलाकि योजनां के प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। यदि जागरूकता बढ़ाने, बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने तथा ऋण सीमा में वृद्धि जैसे सुधार किए जाएँ, तो यह योजना और अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

8. संदर्भ

1. शर्मा, एस., वर्मा., पी., एट ऑल. (2025). *"किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय समावेशन का द्वार खोलनाः जोखिम, लाभ और संस्थागत विश्वास का अंतर्संबंध".* पर्यावरण विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल.
2. त्रिपाठी, जी., धोडिया, ए., राठोर, वी., एट. ऑल., (2023). *"भारत में सरकारी कृषि योजनाएँः एक समीक्षा"* एशियन जर्नल ऑफ एर्गीकल्चरल एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी.
3. सिंह, एम., और राठोर, (2023). *"भारत में कृषि योजनाएँः एक समीक्षा"* एशियन जर्नल ऑफ एर्गीकल्चरल एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी.
4. भट्टाचार्जी, पी. और शर्मा ए. (2020), *"भारत के नागालैण्ड के दीमापुर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड के कृषि व्यवसाय विश्लेषण की स्थिति"* प्लांट आर्काइव्स,.
5. वेरीया, ए., (2020). *"भारतीय कृषि में किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तगर्त सभी किसानों को शामिल करने के लिए आई.सीटी का अनुप्रयोग".* आईसीटी इंडिया वर्किंग पेपर.

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.